

तूफान 'अर्नब' का खतरा बढ़ा

संवाददाता
चेन्नई। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी और मध्य-पूर्वी हिस्से में बना चक्रवाती तूफान 'अर्नब' लगातार शक्तिशाली हो रहा है। इसे देखते हुए तमिलनाडु के तटीय जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सात बंदरगाहों पर तीसरे नंबर का तूफान चेतावनी संकेत लगाया गया है, जबकि मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को नागपट्टिनम जिले में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मयिलादुथुराई, तिरुवारूर, तंजावुर, पुदुकोट्टई और रामनाथपुरम जिलों में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं, मंगलवार को नीलगिरि, कोयंबटूर, डिंडीगुल, तिरुपुर और कन्याकुमारी जिलों में मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया गया



- भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने के निर्देश
- 28 अक्टूबर को तट से टकरा सकता है चक्रवात
- कोयंबटूर के रिहायशी इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित

कि उत्तर-पूर्वी मानसून के दौरान 'अर्नब' पहला चक्रवाती तूफान है। इसके लगातार मजबूत होने और सोमवार मध्यरात्रि तक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप लेने की संभावना है। चक्रवात के खतरे को

देखते हुए तमिलनाडु और पुडुचेरी के बंदरगाहों पर चेतावनी संकेतों में बदलाव किया गया है। पहले नौ बंदरगाहों पर दूसरे नंबर का तूफान चेतावनी संकेत लगाया गया था। अब चेन्नई, एन्नोर, कट्टपल्ली, नागपट्टिनम, कुड्डालोर, पुडुचेरी और कराईकल सहित सात बंदरगाहों पर तीसरे नंबर का चेतावनी संकेत लगा दिया गया है। वहीं, पंबना और तूतीकोरिन बंदरगाहों पर दूसरे नंबर का चेतावनी संकेत बरकरार है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के सक्रिय होने के बाद तमिलनाडु के मत्स्य पालन एवं मछुआरा कल्याण विभाग ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों से मोटर चालित नावों के जरिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने गए मछुआरों को तत्काल तट पर लौटने की सलाह दी है। साथ ही अगले आदेश तक

मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने का निर्देश दिया गया है। पुडुचेरी सरकार ने भी एहतियात के तौर पर मछुआरों के समुद्र में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इधर, कोयंबटूर शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जलाशय लबाब बर गए हैं। जलाशयों का पानी निचले इलाकों और आसपास की रिहायशी बस्तियों में घुसने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होने के कारण बारिश के पानी के साथ गंदा पानी भी सड़कों और घरों में प्रवेश कर गया है। इससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोयंबटूर के सेल्वपुरम-सुंडक्कामुथूर रोड स्थित सेल्वा चिंतामणि तालाब से अचानक बड़ी मात्रा में पानी निकलकर आसपास के रिहायशी इलाकों में घुस गया। तालाब के निचले हिस्से से पानी का रिसाव होने के साथ बारिश के पानी में गंदा पानी मिलने से स्थिति और गंभीर हो गई है। कई घरों और आसपास के इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। इससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।

सीएम फडणवीस ने संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर महाराष्ट्र में विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देश

- नवंबर 2026 से फरवरी 2027 तक चलेगा 'हर घर संत रविदास विचार
- विकसित महाराष्ट्र' अभियान; शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समता और जनजागरण पर रहेगा जोर



संवाददाता
मुंबई। संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर महाराष्ट्र में नवंबर 2026 से फरवरी 2027 तक 'हर घर संत रविदास विचार-विकसित महाराष्ट्र' विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभियान को व्यापक स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास महाराज के मानवता, समानता, करुणा और दुखमुक्त समाज के विचार राज्य के हर वर्ग तक पहुंचाए जाएं। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है। सोमवार को सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री फडणवीस ने की। बैठक में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाल, विधायक रवींद्र चव्हाण, अभियान के राज्य समन्वयक रामेश्वर

नाईक और सहसमन्वयक रवींद्र राठोड़ सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। वन एवं जलसंपदा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। **सामाजिक समरसता और समानता का संदेश घर-घर पहुंचाने की पहल** मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान का उद्देश्य संत रविदास महाराज के विचारों के माध्यम से सामाजिक और वैचारिक जागरूकता बढ़ाना है। जाएं। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है। सोमवार को सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री फडणवीस ने की। बैठक में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाल, विधायक रवींद्र चव्हाण, अभियान के राज्य समन्वयक रामेश्वर

बनाने और निर्धारित कार्यक्रम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। योजना से लेकर जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन तक नियमित समीक्षा के लिए समिति गठित करने की बात भी कही गई। **कुंभ मेले के जरिए व्यापक जनजागरण की योजना** जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष का राज्यस्तरीय मुख्य कार्यक्रम नासिक में आयोजित करने का प्रस्ताव है। कुंभ मेले में देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और नागरिक पहुंचते हैं। ऐसे में अभियान और संत रविदास महाराज के विचारों को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए विशेष जनजागरण गतिविधियां आयोजित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में आने वाले 10 करोड़ से अधिक लोगों तक कम खर्च में प्रभावी तरीके से संदेश पहुंचाने का प्रस्ताव है।

शेष पेज 2 पर...

खास खबर

खरगे ने रामलीला मैदान की रैली में लोगों से बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया तत्काल रोकने की मांग को लेकर एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली में लोगों से बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। खरगे ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि त्योहारों के मौसम में लोग कमरतोड़ महंगाई से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि करोड़ों भारतीयों का मत देने का संवैधानिक अधिकार खतरे में है। इसके लिए उन्होंने आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। खरगे ने कहा कि सभी विपक्षी दलों की मांग है कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें और एसआईआर की प्रक्रिया तत्काल रोक दी जाए। इन मांगों को लेकर एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली आयोजित की जाएगी।



अरुणाचल प्रदेश के हिंसा प्रभावित पासीघाट में हुई आरएएफ की तैनाती

इटानगर। अरुणाचल प्रदेश के 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' का विरोध करते हुए, पूर्वी सियांग जिले के युवाओं द्वारा पासीघाट में भारी हिंसा किए जाने के बाद, केंद्र सरकार ने कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और सीआरपीएफ की दो कंपनियों को वहां तैनात किया है। रिपोर्ट के अनुसार, रविवार की शाम से ही आरएएफ की तैनात शुरू हो गयी है। लगभग 250 आरएएफ जवान पासीघाट पहुंचे, जिन्हें भारतीय वायु सेना के विमान से वहां पहुंचाया गया था। सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार को दिए गए निर्देश के बाद, लगभग 250 जवानों वाली आरएएफ की दो कंपनियों को नवी मुंबई से भारतीय वायु सेना के एक ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए एयरलिफ्ट किया गया। ये टुकड़ियां रविवार को ही पासीघाट पहुंच गईं। इनकी वहां तैनाती कर दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग इलाके में मौजूदा हालात को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स को पासीघाट भेजा गया है।

राजनाथ सिंह 28-29 अक्टूबर को फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली। फिलीपींस के सेबू में 28 से 29 अक्टूबर तक होने वाली 13वीं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग (एडीएमएम)-प्लस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। वह क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर फोरम को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री एडीएमएम-प्लस के दौरान हिस्सा लेने वाले देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे आसियान देशों के साथ चल रहे रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे और रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के तरीके खोजेंगे, क्योंकि यह सदस्य देशों के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का एक प्लेटफॉर्म है। दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) और उसके 8 संवाद भागीदारों का एक महत्वपूर्ण रक्षा मंच है। वर्ष 2010 में स्थापित इस मंच में 10 आसियान देश ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीपुल्स रिपब्लिक, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और वियतनाम और 8 प्लस देश भारत, चीन, रूस, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हैं।



पंजाब में कानून-व्यवस्था को लेकर

भाजपा का भगवंत मान सरकार पर हमला

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पंजाब की आम आदमी पार्टी (आआपा) सरकार पर अपराध नियंत्रण में पूरी तरह से विफल रहने का आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और राज्य में हत्या, नशे तथा अन्य आपराधिक घटनाओं से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोमवार को यहां पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि पंजाब में अपराधियों के हाौसले बढ़ रहे हैं और आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने राज्य के मौजूदा हालात के लिए भगवंत मान सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। भाटिया ने आआपा पर हमला करते हुए उसे अराजक अपराध पार्टी करार



दिया। भाटिया ने पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान हुई हत्याओं की तीन घटनाओं का उल्लेख किया। इनमें पहली घटना पंजाब के मोगा जिले में हुई दो युवकों की हत्या की थी। भाटिया के अनुसार हथियारों से लैस हमलावर बिना नंबर प्लेट वाली काली स्कॉर्पियो गाड़ी में पहुंचे और दो युवकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इस घटना में दोनों युवकों की मौत हो गई, जबकि कई

अन्य लोग घायल हुए। उन्होंने इस घटना का हवाला देते हुए राज्य में अवैध हथियारों की उपलब्धता और खुलेआम गोलीबारी को लेकर सवाल उठाए। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी, हथियारों से लैस हमलावर और दिनदहाड़े हुई गोलीबारी जैसी परिस्थितियां राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं से आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। भाटिया ने पंजाब में अपराध की घटनाओं के साथ-साथ नशे की समस्या का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हत्या, नशे और अन्य गंभीर घटनाओं को रोकने में सरकार प्रभावी साबित नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अपराध की घटनाओं से पीड़ित लोगों को न्याय और सुरक्षा मिलनी चाहिए।

मानहानि मामले में राहुल गांधी दोषमुक्त, सुल्तानपुर कोर्ट से मिली बड़ी राहत

- छह साल पुराने मुकदमे में अदालत ने शिकायतकर्ता को 'पीड़ित व्यक्ति' मानने से किया इनकार, फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे विजय मिश्रा



संवाददाता
सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने सोमवार को छह साल पुराने मुकदमे में उन्हें दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने 49 पन्नों के आदेश में शिकायतकर्ता विजय मिश्रा को 'पीड़ित व्यक्ति' की श्रेणी में नहीं माना। साथ ही कहा कि राहुल गांधी के बयान का शिकायतकर्ता पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। शिकायतकर्ता की ओर से पेश गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास पाया गया। फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर, पटाखे फोड़कर और नारेबाजी कर खुशी जताई। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कहा कि अदालत ने शिकायतकर्ता को

पीड़ित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं माना है। वहीं, विजय मिश्रा ने कहा कि उन्होंने अभी फैसले की प्रति नहीं देखी है। वह वकीलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद कानूनी राय के आधार पर ऊपरी अदालत में अपील दायर करेंगे। **2018 में दर्ज हुई थी मानहानि की शिकायत** मामला आठ मई 2018 का है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बंगलुरु में राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। इससे नाराज भाजपा नेता और तत्कालीन जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष विजय मिश्रा ने चार अगस्त 2018 को मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब किया था। वह 20 फरवरी 2024 को अदालत में पेश हुए, जहां उन्हें जमानत मिली।

शेष पेज 2 पर...

सेनाओं के लिए 2.12 लाख करोड़ रुपये के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी

- कुल प्रस्तावों में से लगभग 82 फीसदी हथियारों की खरीद भारतीय उद्योगों से की जाएगी



संवाददाता
नई दिल्ली। भारतीय सेनाओं के लिए 2.12 लाख करोड़ रुपये के सैन्य उपकरण खरीदे जाएंगे, जिसके लिए सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसपी) की बैठक में मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार से मंजूर किये गए कुल पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों में से लगभग 82 फीसदी हथियारों की खरीद भारतीय उद्योगों से की जाएगी। केंद्र सरकार ने अलग-अलग पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को लगभग 2,12,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर जरूरी चीजों की स्वीकृति (एशोरन) यानी सैद्धांतिक रूप से प्रशासनिक मंजूरी दी है। इस रकम से भारतीय सेना के लिए हार्ड मोबिलिटी व्हीकल, सेल्फ-प्रोपेल्ड ट्रैकड गन सिस्टम, गन शॉट रिसॉन्स सिस्टम, लाइट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, प्लेटफॉर्म बेड काउंटर अनमैड एरियल सिस्टम, अनमैड एरियल सिस्टम ब्रिक लॉन्ग रेंज,

सर्विलांस यूएवी, इंटीग्रेटेड सर्विलांस एंड स्ट्राइक सिस्टम और लॉन्ग रेंज कामिकेज ड्रोन सिस्टम खरीदे जाएंगे। सेना के लिए हार्ड मोबिलिटी व्हीकल मुश्किल इलाकों में ऑपरेशनल क्षमता, लॉजिस्टिक सपोर्ट और मोबिलिटी को बढ़ाएंगे। सेल्फ-प्रोपेल्ड ट्रैकड गन सिस्टम, मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन को मैचिंग मोबिलिटी और फायरपावर देगा। गन शॉट रिसॉन्स सिस्टम फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम करेगा, जो फोर्स को रियल-टाइम सिचुएशनल अवेंसरेनेस देगा। लाइट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर लाइट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स दोनों ही टोही और सर्विलांस, कॉम्बैट, सैनिकों की सर्च

और रेस्क्यू, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ वगैरह के लिए करेंगे। इसी तरह वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस हाई मोबिलिटी व्हीकल मुश्किल इलाकों में ऑपरेशनल क्षमता, लॉजिस्टिक सपोर्ट और मोबिलिटी को बढ़ाएंगे। सेल्फ-प्रोपेल्ड ट्रैकड गन सिस्टम, मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन को मैचिंग मोबिलिटी और फायरपावर देगा। गन शॉट रिसॉन्स सिस्टम फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम करेगा, जो फोर्स को रियल-टाइम सिचुएशनल अवेंसरेनेस देगा। लाइट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर लाइट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स दोनों ही टोही और सर्विलांस, कॉम्बैट, सैनिकों की सर्च

शेष पेज 2 पर...

संपादकीय



विदेशी साजिशों के आरोपों से कब तक चलेगी राजनीति?

विदेशी ताकतों की साजिश' का आरोप भारतीय राजनीति में लंबे समय से इस्तेमाल होता रहा है। सत्ता में बैठे दल अक्सर अपने विरोधियों की आलोचना और आंदोलनों को विदेशी हस्तक्षेप से जोड़ने की कोशिश करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई जैसे नेताओं पर सीआईए से जुड़े होने के आरोप लगाए गए थे। जवाहरलाल नेहरू के समय में भी समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया को विदेशी एजेंट बताने की कोशिशें हुई थीं। इससे स्पष्ट होता है कि विरोधियों की देशभक्ति पर सवाल उठाना भारतीय राजनीति की पुरानी प्रवृत्ति रही है। आज भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं पर भी इसी तरह के आरोप लगाने का सवाल उठ रहा है, क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विदेशी साजिशों से जोड़कर निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और वहां विभिन्न लोगों से उनकी मुलाकातों को लेकर सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया जाता है कि विदेशों में भारत के खिलाफ रणनीति तैयार की जाती है और देश लौटकर उसे राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर तीखे राजनीतिक हमले किए हैं। उन्होंने कांग्रेस को परजीवी बताते हुए एक ही असफल राजनीतिक चेहरे को बार-बार प्रस्तुत करने की बात कही। हालांकि, नाम लिए बिना किए ऐसे कटाक्षों का निशाना किसे बनाया जा रहा है, यह राजनीतिक संदर्भ में स्पष्ट माना जाता है। सवाल यह है कि क्या देश के प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच राजनीतिक मतभेदों की अभिव्यक्ति इसी भाषा में होनी चाहिए? लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। विपक्षी नेता सरकार की नीतियों, आर्थिक परिस्थितियों, बेरोजगारी, महंगाई और नागरिक समस्याओं पर सवाल उठाते हैं। सरकार को भी अपने कामकाज का हिसाब देना चाहिए। यदि किसी नेता पर देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने के ठोस प्रमाण हैं, तो आरोपों को राजनीतिक मंचों पर दोहराने के बजाय कानून के अनुसार जांच कराई जानी चाहिए। पर्याप्त सबूत मिलने पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और अंतिम निर्णय न्यायालय को करना चाहिए। केवल आरोप लगाकर किसी व्यक्ति को दोषी मान लेना लोकतांत्रिक मूल्यों और न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि विरोध-प्रदर्शन और आंदोलन अलग-अलग दौर में सत्ता के लिए चुनौती बनते रहे हैं। मार्च 1974 में बिहार में हुए आंदोलन के दौरान जनसंघ से जुड़े युवा नेताओं सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद सहित अन्य नेताओं की गतिविधियों का उल्लेख करते हुए उस दौर की राजनीति पर भी सवाल उठाए जाते हैं। राजभवन के घेराव, मुख्यमंत्री के काफिले के विरोध और विधानसभा परिसर से जुड़े घटनाक्रमों ने उस समय राजनीतिक तनाव बढ़ाया था। जयप्रकाश नारायण ने भी हर विरोध-प्रदर्शन को क्रांति मानने से इनकार किया था। इतिहास के इन प्रसंगों से यह समझना जरूरी है कि राजनीतिक आंदोलनों का मूल्यांकन समान मानदंडों पर होना चाहिए। यदि अतीत में विरोधियों के उग्र प्रदर्शनों को राजनीतिक संघर्ष माना गया, तो वर्तमान में विपक्ष के हर प्रदर्शन को अराजकता या देशविरोधी गतिविधि बताना भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों को लेकर भाजपा की आलोचनाओं के बीच यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी आंदोलन के दौरान कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका निर्णय तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। किसी सरकारी भवन में प्रवेश करना या धरना देना नियमों के उल्लंघन का मामला हो सकता है, लेकिन हर ऐसी घटना को विदेशी साजिश से जोड़ना अलग तरह का गंभीर आरोप है। दोनों के बीच अंतर करना आवश्यक है। राजनीतिक विरोध को अपराध घोषित करने और वास्तविक आपराधिक गतिविधियों की जांच करने के बीच स्पष्ट सीमा होनी चाहिए। विदेशी फंडिंग और जॉर्ज सोरोस का मुद्दा भी इसी बहस का हिस्सा रहा है। सोरोस के बयानों और भारत से संबंधित उनकी राजनीतिक टिप्पणियों को लेकर सत्तारूढ़ दल ने कई बार आपत्ति जताई है। लेकिन यदि सरकार को लगता है कि किसी विदेशी व्यक्ति या संगठन की गतिविधियां भारतीय कानून के विरुद्ध हैं, तो उसे उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर जांच और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। विदेशी वित्तपोषण पर रोक लगाने के लिए भी संबंधित कानूनों और निरधारित प्रक्रियाओं का पालन जरूरी है। केवल किसी व्यक्ति का नाम बार-बार लेने से आरोप प्रमाणित नहीं हो जाते। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कथित साजिश में कौन शामिल है, धन कहाँ से आया और उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना और देश के खिलाफ साजिश को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता। शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन संवैधानिक लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

दृष्टिकोण: आम आदमी क्यों भुगतते भ्रष्ट व्यवस्था की सजा

डॉ.सुधाकर आशावादी

आम आदमी की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आम आदमी जीवन भर संघर्ष करता रहता है। अधिकांश आबादी का सपना होता है, कि उसके सर पर अपनी छत हो, सो जोड़, तोड़ करके वह जैसे तैसे अपने लिए मकान की व्यवस्था करता है, रोजगार के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना करता है। ऐसे में यदि आम आदमी के मकान को अवैध निर्माण बताकर ध्वस्त करने की बात की जाए, तो उसके सम्मुख जीवन मरण का प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है। देश के विभिन्न नगरों व महानगरों में आम आदमी इसी आशंका से ग्रस्त है, कि कहीं उसके मकान को अवैध



निर्माण घोषित करके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही न कर दी जाए। बहरहाल सत्य यही है, कि आम आदमी के सपने को जहां निजी कॉलोनाइजर पूरा करते हैं, वहीं सरकारी एजेंसियां भी उनका भरपूर साथ निभाती हैं, जिन मकानों को अवैध निर्माण बताया

जाता है,उनमें से अधिकांश निर्माण सरकारी भ्रष्ट व्यवस्था की सरपरस्ती में ही होते हैं। चाहे आवास विकास परिषद से जुड़ी सम्पत्तियाँ हों अथवा विकास प्राधिकरणों से जुड़ी सम्पत्तियाँ, चाहे निजी प्लांटिंग,इनमें नियमानुसार निर्माण हो रहा है या नहीं, इसका

पेज 1 का शेष...

सीएम फडणवीस ने...

सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता मंत्री संजय शिरसाट ने समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को एक साझा मंच पर सम्मानित करने का सुझाव दिया। वहीं, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे ने संत रविदास महाराज के नाम पर विशेष योजना शुरू करने की बात रखी। इसमें अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, नए क्षेत्रों में काम करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के उपाय शामिल करने का सुझाव दिया गया।

स्कूलों, कॉलेजों और गांवों में होंगे विविध कार्यक्रम

अभियान के तहत राज्य की 1,08,139 स्कूलों, 5,841 कॉलेजों, 65 विश्वविद्यालयों और 11,150 सार्वजनिक पुस्तकालयों को जोड़ने की योजना है। शिक्षण संस्थानों में निबंध, वक्तुत्व, प्रश्नोत्तरी, संत साहित्य वाचन, शोध और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विद्यार्थियों में सामाजिक समानता और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक सेवा गतिविधियां भी होंगी। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच, रक्तदान शिविर, नेत्र और दंत जांच, महिला एवं बाल स्वास्थ्य, पोषण, नशामुक्ति तथा स्वच्छता जागरूकता शामिल होंगी। श्रम के महत्व को रेखांकित करने के लिए 'श्रमवीर सम्मान', कारीगरों के उत्पादों की प्रदर्शनी, महिला आर्थिक स्वावलंबन कार्यक्रम और युवा सेवा सप्ताह भी आयोजित किए जाएंगे।

650 गांवों में विचारसभा और वृक्षारोपण

योजना के अनुसार, राज्य के 650 गांवों में विचारसभाएं और वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रत्येक जिले में दो प्रचार वाहनों के माध्यम से संत रविदास महाराज के विचारों का प्रचार होगा। वीडियो, पॉडकास्ट, साक्षात्कार और संवाद कार्यक्रमों से भी नागरिकों तक अभियान का संदेश पहुंचाया जाएगा। डिजिटल माध्यमों के तहत 'डिजिटल रविदास 650', ई-ग्रंथालय, डिजिटल प्रश्नोत्तरी और 650 प्रेरणादायी वीडियो कहानियां तैयार करने की योजना है। अभियान के तहत राज्यस्तरीय मुख्य कार्यक्रम 13 और 14 फरवरी 2027 को नासिक में प्रस्तावित है। इसमें बेगमपुरा की संकल्पना, संत संगम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समता महामंच, संत रविदास विरासत प्रदर्शनी, संवाद केंद्र और सामुदायिक अन्नसेवा शामिल होंगे। मुख्य कार्यक्रम के बाद 'समाज कुंभ' के माध्यम से विभिन्न सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को एक मंच पर लाकर समानता, बंधुता, सामाजिक एकता और मानवता के विचारों के प्रसार की योजना भी बनाई गई है।

मध्य रेलवे की...

इस घटना ने संवेदनशील तकनीकी उपकरणों के नियमित रखरखाव, वायरिंग की जांच और सुरक्षा मानकों के पालन की अहमियत को फिर सामने ला दिया है। रेलवे प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और क्या नियमित निरीक्षण के दौरान किसी संभावित तकनीकी खराबी के संकेत मिले थे। साथ ही, जांच में यदि रखरखाव संबंधी कोई कमी सामने आती है, तो उसके लिए जिम्मेदारी तय कर सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए।

लोकल सेवाएं प्रभावित, यात्रियों को भीड़ और देरी से जूझना पड़ा

सुबह के व्यस्त समय में रेल सेवाएं बाधित होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। लोकल ट्रेनों में भारी भीड़ के बीच फंसे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में ट्रेनें लंबे समय तक रुकी रहने पर कुछ यात्री पटरियों पर उतरकर पैदल चलने का जोखिम उठाते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। रेलवे प्रशासन को ऐसी स्थिति में यात्रियों की सुरक्षित निकासी, वैकल्पिक परिवहन और स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। यात्रियों को यह भी बताया जाना जरूरी है कि ट्रेन सेवाएं कब तक बहाल होने की संभावना है और आगे की यात्रा के लिए कौन से विकल्प उपलब्ध हैं।

रखरखाव के लिए मेगा ब्लॉक

खास बात यह है कि रिवार को ही मध्य रेलवे ने रखरखाव कार्यों के लिए मेगा ब्लॉक लिया था। इसके अगले ही दिन इतनी बड़ी तकनीकी समस्या सामने आने से यात्रियों में नाराजगी बढ़ गई है। लोगों का सवाल है कि नियमित मेंटेनेंस के बावजूद रेलवे ऐसी स्थितियों को रोकने में क्यों नाकाम रहा। यात्री विजय कुमार ने कहा कि मध्य रेलवे प्रशासन को कांजूरमार्ग रिले रूम में आग लगने की घटना की विस्तृत जांच कराकर सिग्नलिंग उपकरणों के रखरखाव, सुरक्षा प्रोटोकॉल, वैकल्पिक परिचालन व्यवस्था और यात्री सूचना प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव श्रीवास्तव से अपेक्षा है कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं के कारण यात्रियों को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मानहानि मामले में...

सुकदमे के दौरान करीब 140 पेशियां हुईं और राहुल गांधी को कुल चार बार सुल्तानपुर आना पड़ा। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने की मांग की थी, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। राहुल गांधी का बयान 20 फरवरी 2026 को दर्ज किया गया। छह अक्टूबर को अंतिम बहस शुरू हुई और 12 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हो गई।

14 मिनट में पूरी हुई अदालती कार्यवाही

सोमवार सुबह 11:19 बजे राहुल गांधी एमपी-एमएलए कोर्ट के कक्ष में पहुंचे और 11:33 बजे बाहर निकल गए। करीब 14 मिनट में कार्यवाही पूरी हुई, जिसमें लगभग 10 मिनट तक न्यायाधीश ने फैसला पढ़ा। इस दौरान उनके साथ अधिवक्ता काशीनाथ शुक्ला, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आरएस चौमा, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने फैसले पर संतोष जताया। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने कहा कि फैसले की प्रति देखने और कानूनी सलाह लेने के बाद वह आगे की कार्रवाई तय करेंगे। उन्होंने ऊपरी अदालत में अपील दायर करने की बात कही।

सर्वेक्षण करने तथा अवैध निर्माण होने पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने का अधिकार सम्बंधित नगर से जुड़े विकास प्राधिकरणों का होता है, किन्तु यदि अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने का दायित्व धारण करने वाली एजेंसियां ही अपने कर्तव्य से विमुख होकर अवैध निर्माण अपनी नाक के नीचे कराएं, तो इसका दोषी कौन होगा, क्या अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप अपने लिए आवास की व्यवस्था करने वाला आम आदमी या विकास प्राधिकरणों के वे अधिकारीगण, जिनके कार्यकाल में तथाकथित अवैध निर्माण की स्थिति बन गई है। आम आदमी यह नहीं समझ पा रहा है, कि जीवन भर की कमाई से अपने सर पर छत जुटाने के उपरांत भी क्या वह अपने घर में

सुरक्षित है, यदि नहीं, तो क्या उसे बेघर कर दिया जायेगा। देश भर में समय समय पर इस प्रकार की स्थिति आती रहती है, कि जब बड़ी बड़ी कॉलोनियां अवैध घोषित की जाती हैं तथा चुनावों के समय उन कॉलोनियों को वैध घोषित कर दिया जाता है। दिल्ली जैसे महानगर में ऐसा अनेक बार हुआ है। विचारणीय बिंदु यह भी है, कि अवैध निर्माणों की परिभाषा में जिन कॉलोनियों को चिन्हित किया जाता है, उन कॉलोनियों में विद्युत, पानी व रसोई गैस की सप्लाई किस आधार पर सुनिश्चित होती है? क्या विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों, विद्युत वितरण कंपनियों को किसी भी कॉलोनी के अवैध होने से कोई सरोकार नहीं, यदि उनकी संलिप्तता अवैध कॉलोनियों के निर्माण में है, तो उनके भ्रष्टाचार की सजा आम आदमी क्यों भुगते?



एल.आई.सी
भारतीय जीवन बीमा
से संबंधित किसी भी
जानकारी या समस्या
समाधान हेतु संपर्क करें।
-भारत सिंह
मो. 9967255741

महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञापन प्रति के स्वीकृति पूर्व एहतियातन बरती जाने के बावजूद, उसमें अंतर्भूत बाते जाँचना संभव नहीं है। ऐसी अंतर्भूत बातों के लिए दैनिक स्वर्णिम प्रदेश के अंतर्गत समाचार पत्र या प्रकाशनों में आनेवाली कंपनियां, संस्थाएं या व्यक्तिगत विज्ञापनों के साथ हुए किसी भी प्रकार के व्यवहार के लिए समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं है।

आज का राशिफल



मेघ: नई योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अनुकूल है। व्यापारिक सौदों में बड़ा फायदा हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। वित्तीय लाभ मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी। शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

वृषभ: सहकर्मियों का सहयोग कार्य को आसान बनाएगा। व्यापार में नया मोड़ आएगा, लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा। रुका पैसा वापस आ सकता है। सेहत सामान्य रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे। चंद्र देव को अर्घ्य दें।

मिथुन: आपके काम की दफ्तर में प्रशंसा होगी। व्यावसायिक यात्राओं से फायदा मिलेगा। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। आय में सुधार की संभावना है। मानसिक शांति मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी। ॐ नमः शिवाय का जप करें।

कर्क: पदोन्नति या नए अधिकार मिल सकते हैं। व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। परिजनों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे। सेहत उत्तम रहेगी, ऊर्जा महसूस करेंगे। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।

सिंह: आपके फैसले कार्यस्थल पर सराहे जाएंगे। व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी। प्रेम जीवन में खुशी और नवीनता रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। शारीरिक रूप से चुस्त रहेंगे। पार्वती जी की पूजा करें।

कन्या: दफ्तर में सजगता और सावधानी से काम लें। व्यापारिक लेन-देन में सतर्कता बरतें। परिजनों के साथ बातचीत में संयम रखें। बजट के अनुसार ही खर्च करें। खान-पान का ध्यान रखें, सेहत सामान्य रहेगी। किसी गरीब को अनाज का दान करें।

तुला: प्रभाव और दायरा बढ़ने के संकेत हैं। साझेदारी के कारोबार से लाभ होगा। पारिवारिक सुख-सौहार्द बना रहेगा। धन आगमन का मार्ग सुगम होगा। सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

वृश्चिक: विरोधियों पर विजय मिलेगी, काम बनेंगे। व्यापार में मुनाफे के नए स्रोत बनेंगे। परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। अचानक धन लाभ होने के योग हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, तनाव से बचें। शिव जी को आंकड़े के फूल चढ़ाएं।

धनु: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में नए निवेश का मन बना सकते हैं। संतान पक्ष से खुशी का समाचार मिलेगा। आय में वृद्धि के स्पष्ट योग हैं। ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी।

मकर: जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, धैर्य रखें। कागजी काम ध्यानपूर्वक निपटाएं। परिवार में मिलकर मसले सुलझाएं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। विश्राम करें, थकावट महसूस हो सकती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं।

कुंभ: बुद्धिमानी से सभी कार्य आसानी से बनेंगे। नए सौदों पर मुहर लग सकती है। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती रहेगी।

सफेद फूल जल में प्रवाहित करें।

मीन: आपके सुझावों को सराहना मिलेगी। व्यापार में लाभ के मौके बढ़ेंगे। घर में मांगलिक माहौल रहेगा। धन संचय में सफलता मिलेगी। मानसिक शांति और सेहत अच्छी रहेगी।

आज से रेलवे आरक्षण काउंटरों पर भी मिलेगा वैकल्पिक यात्रा बीमा 45 पैसे के प्रीमियम पर मिलेगा 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर

संवाददाता

मुंबई। भारतीय रेल ने 27 अक्टूबर 2026 से रेलवे आरक्षण काउंटरों पर भी वैकल्पिक यात्रा बीमा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अब यात्री यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटरों से आरक्षित टिकट बुक करते समय 10 लाख रुपये तक का यात्रा बीमा लेने का विकल्प चुन सकेंगे। इससे पहले यह सुविधा आईआरसीटीसी के माध्यम से ई-टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध थी। इस योजना के तहत यात्री अपनी इच्छा से बीमा का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर देना होगा और निर्धारित प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। मौजूदा योजना के अनुसार, प्रति यात्री बीमा प्रीमियम 45 पैसे है।

मृत्यु और दिव्यांगता पर 10 लाख रुपये तक का कवर
रेल दुर्घटना या अप्रिय घटना में मृत्यु: 10 लाख रुपये
स्थायी पूर्ण दिव्यांगता: 10 लाख रुपये
स्थायी आंशिक दिव्यांगता: 7.5 लाख रुपये तक
चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती का खर्च: 2 लाख रुपये तक
पार्थिव शरीर के परिवहन का खर्च:



10,000 रुपये
बीमा कवरेज आईआरसीटीसी के माध्यम से ई-टिकट बुक करने वाले यात्रियों पर लागू मौजूदा वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार होगा। मोबाइल पर मिलेगी पॉलिसी की जानकारी बीमा का विकल्प चुनने वाले यात्रियों को पॉलिसी का विवरण उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। रेलवे आरक्षण कर्मचारी यात्रियों को बीमा का विकल्प चुनने में सहायता करेंगे। साथ ही प्रीमियम के उचित संग्रह और यात्रियों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है। रेलवे के अनुसार, मामूली प्रीमियम पर उपलब्ध यह वैकल्पिक बीमा सुविधा रेल यात्रा के दौरान अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

महाराष्ट्र के आठों विभागों में आधुनिक दवा जांच मशीनें शुरू

सवाददाता

मुंबई। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टरों, बुनियादी सुविधाओं और दवाओं की आपूर्ति के साथ-साथ दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के आठों विभागों में आधुनिक दवा जांच मशीनें (ड्रग डिटेक्शन मशीन) शुरू की हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने बताया कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आपूर्ति की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

दवाओं के नमूनों की होगी प्राथमिक जांच
इस व्यवस्था के तहत दवाओं के नमूनों की प्राथमिक जांच की जाएगी। जिन नमूनों में गुणवत्ता को लेकर संदेह या खामियां मिलने की आशंका होगी, उन्हें आगे की विस्तृत जांच के लिए भेजा जाएगा। इससे



दवाओं की गुणवत्ता पर नियमित निगरानी रखने, जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने मशीन का प्रदर्शन देखा
स्वास्थ्य भवन में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान मंत्री आबिटकर ने इस पहल की जानकारी दी। इस अवसर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त डॉ. संजय काटकर और डॉ. सुनील भोकरे उपस्थित थे। कार्यक्रम में आधुनिक ड्रग डिटेक्शन मशीन के कामकाज का प्रदर्शन भी किया गया।

500 करोड़ रुपये के कथित भुगतान के आरोपों की जांच के लिए SIT गठित

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर मुंबई पुलिस ने वायरल ऑडियो क्लिप से जुड़े 500 करोड़ रुपये के कथित भुगतान के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। 35 मिनट की इस कथित ऑडियो क्लिप में दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने मराठा आरक्षण आंदोलन को संभालने के लिए एकनाथ शिंदे को 500 करोड़ रुपये दिए थे और यह रकम कथित तौर पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के माध्यम से मनोज जारंगे-पाटिल तक पहुंचाई गई थी। मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने सोमवार को SIT गठन का आदेश जारी किया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिण क्षेत्र) शैलेश बलकवड़े टीम का नेतृत्व करेंगे। पुलिस उपायुक्त विजयकांत सागर (जोन-3) और बजरंग बनसोडे (साइबर सेल) इसके सदस्य

होंगे।
बलकवड़े की नियुक्ति पर उठे सवाल
SIT का नेतृत्व शैलेश बलकवड़े को सौंपे जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जाता है कि जालना में सितंबर 2023 में मराठा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी के तबादले के पश्चात बलकवड़े को वहां तैनात किया गया था। उस समय मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों को शांत करने में उनकी भूमिका रही थी। इसके बाद भी उनकी जारंगे-पाटिल से बातचीत होती रही थी।
जारंगे और श्रीकांत शिंदे ने आरोपों से किया इनकार
मनोज जारंगे-पाटिल और श्रीकांत शिंदे, दोनों ने कथित भुगतान के आरोपों को खारिज किया है और मामले की जांच की मांग की है। पिछले सप्ताह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारंगे-पाटिल ने आरोप

वाढवण बंदर के पास बनेगा विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय कृषि बाजार निवेश के लिए DBS बैंक से पहल करने की अपील

महाराष्ट्र सरकार, DBS बैंक और IICare फाउंडेशन के बीच त्रिपक्षीय समझौता, कृषि निर्यात, हरित वित्त और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर जोर

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाढवण बंदर के पास विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय बहुउद्देशीय कृषि बाजार विकसित करने की योजना है। इसके लिए सिंगापूर के निवेशकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और रणनीतिक भागीदारों के माध्यम से निवेश लाने के लिए DBS बैंक से पहल करने की अपील की गई है। सोमवार को पणन एवं राजशेषाचार मंत्री जयकुमार रावल ने सहाय्यी अतिथिगृह में DBS बैंक और IICare फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह आग्रह किया।

कृषि व्यापार और निर्यात को मिलेगा बढ़ावा
प्रस्तावित कृषि बाजार में एकीकृत कोल्ट



चेन, आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं, गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था और वैश्विक बाजारों से सीधा संपर्क उपलब्ध कराने की योजना है। इससे कृषि व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने के साथ फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने तथा किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। मंत्री रावल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नदी पुनर्जीवन, टिकाऊ जल प्रबंधन, भूजल पुनर्भरण, सूखा निवारण और जलवायु-अनुकूल खेती के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय हरित वित्त और तकनीकी सहयोग महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आधुनिक सिंचाई, सटीक कृषि तकनीक,

माहिम चौपाटी पर फिर सजा मुंबई का पहला सी-फूड प्लाजा, महिला बचत समूहों के स्टॉल शुरू

संवाददाता

मुंबई। मुंबईकरों और पर्यटकों को ताजा, स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण मछली से बने व्यंजनों का स्वाद उपलब्ध कराने के लिए माहिम चौपाटी स्थित मुंबई का पहला सी-फूड प्लाजा एक बार फिर शुरू हो गया है। शनिवार, 24 अक्टूबर 2026 से यहां महिला बचत समूहों के स्टॉल शुरू किए गए हैं। यह प्लाजा सप्ताह में बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को खुला रहेगा। इस अवसर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गटनेता एवं जी-उत्तर प्रभाग समिति के अध्यक्ष यशवंत किल्लेदार, मराठी अभिनेता कमलाकर सातपुते, जी-उत्तर विभाग के सहायक आयुक्त योगेश देसाई सहित महानगरपालिका के अधिकारी और महिला बचत समूहों की सदस्य उपस्थित थीं।

आकर्षक सजावट और सेल्फी पॉइंट की सुविधा
सी-फूड प्लाजा में आकर्षक रंग-सज्जा, रोशनी, सेल्फी पॉइंट और आरामदायक बैठने की व्यवस्था की गई है। यहां आने वाले नागरिक स्थानीय कोली गीतों और पारंपरिक कोली व्यंजनों का आनंद भी ले

बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मिलेगा ताजा समुद्री भोजन, कोली संस्कृति और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल



सकेगे। महिला बचत समूहों को मत्स्य उत्पादों पर आधारित प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे अपने व्यवसाय को विकसित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

कोली संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा
मुंबई के कोलीवाड़ों के सौंदर्योत्कर्षण, महिला बचत समूहों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माहिम चौपाटी

नाशिक में 517 लोगों ने एक साथ किया शंखनाद, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम

सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों के बीच गोदावरी तट पर सामूहिक शंखनाद, पालकमंत्री गिरीश महाजन ने प्रतिभागियों को दी बधाई

संवाददाता

नाशिक। महाराष्ट्र के नाशिक में गोदावरी नदी के तट पर 517 लोगों ने एक साथ शंखनाद कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस अवसर पर पालकमंत्री गिरीश महाजन उपस्थित रहे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि ऋषिकेश नाग ने इस रिकॉर्ड की घोषणा की। सिंहस्थ कुंभ मेला प्राधिकरण और अनंत विजय शंखनाद पथक के संयुक्त तत्वावधान में कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा और सामूहिक सहभागिता का प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। पालकमंत्री गिरीश महाजन ने रिकॉर्ड बनाने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि देश



की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली है। उन्होंने वर्ष 2027 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के मद्देनजर नागरिकों से तैयारियों में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की। साथ ही श्रद्धालुओं का आत्मीय स्वागत करने और स्वच्छता, यातायात तथा अन्य सुविधाओं के सुचारु संचालन के लिए प्रशासन को सहयोग देने का आह्वान किया। सिंहस्थ कुंभ मेले की पूर्व तैयारियों के महत्वपूर्ण चरण के रूप में 31 अक्टूबर को नाशिक के रामकुंड और त्र्यंबकेश्वर में दोपहर 12 बजकर 2 मिनट पर ध्वजारोहण किया जाएगा।

सीएम फडणवीस के निर्देश पर मुंबई पुलिस ने बनाई तीन सदस्यीय टीम, मनोज जारंगे-पाटिल और श्रीकांत शिंदे ने आरोपों को नकारा



लगाया था कि मराठा आरक्षण आंदोलन को बदनाम करने और उसे खत्म करने के लिए दबाव बनाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे उठाने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और यह पता लगाया जाना चाहिए कि इन आरोपों के पीछे कौन है

तथा उनका मकसद क्या है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विवाद सामने आने के बाद मुंबई पुलिस को जांच के निर्देश दिए थे। अब SIT कथित ऑडियो क्लिप, उसमें किए गए दावों और रिकॉर्डिंग से जुड़े हालात की जांच करेगी, ताकि आरोपों की सच्चाई सामने आ सके।

मुंबई एयरपोर्ट पर 1.8 किलो से अधिक गांजा जब्त, दिल्ली की दो महिलाएं गिरफ्तार

संवाददाता

मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने दो अलग-अलग कार्वाइयों में 1.8 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त कर दिल्ली की दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाएं बैंकोंक से मुंबई पहुंची थीं। अधिकारियों को संदेह है कि दोनों का संबंध एक ही अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह से हो सकता है। इस पहलू की जांच की जा रही है।

पहली महिला के सामान से 910 ग्राम गांजा बरामद
पहली कार्वाई में खुफिया जानकारी के आधार पर बैंकोंक से मुंबई पहुंची दिल्ली निवासी नीतू को रोका गया। उसके चेक-इन बैग और हैंड बैगज की तलाशी के दौरान चार पारदर्शी प्लास्टिक पैकेट मिले, जिनमें कुल 910 ग्राम गांजा रखा था। कस्टम अधिकारियों ने उसका बयान दर्ज किया। विभाग के अनुसार, महिला ने प्रतिबंधित पदार्थ की घोषणा नहीं करने और उसके छिपाकर रखे होने से संबंधित तथ्यों को स्वीकार किया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच जारी है।



और अधिकारियों ने तस्करी नेटवर्क से जुड़े कथित सहयोगियों तथा हैंडलर्स की पहचान करने के प्रयास शुरू किए हैं।

दूसरी महिला के पास से 964 ग्राम गांजा मिला
दूसरी घटना में बैंकोंक से मुंबई पहुंची दिल्ली निवासी रजनी को भी कस्टम अधिकारियों ने रोका। उसके सामान की तलाशी में प्लास्टिक के तीन पैकेटों से लगभग 964 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान उसका आधिकारिक बयान दर्ज किया गया और प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी के बाद उसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। कस्टम विभाग दोनों मामलों की जांच कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि क्या दोनों महिलाएं किसी साझा तस्करी नेटवर्क के लिए काम कर रही थीं और प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति के पीछे कौन लोग शामिल हैं।

महाराष्ट्र में दो नए वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी 14 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के प्रस्ताव भी स्वीकृत

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र में वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य वन्यजीव मंडल की 26वीं बैठक में गढ़चिरोली जिले के कोलामार्का संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने तथा तानसा वन्यजीव अभयारण्य के पास नए विस्तारित तानसा वन्यजीव अभयारण्य को घोषित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही पुणे, रायगढ़, नासिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर और चंद्रपुर जिलों के 14 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए। बैठक में वन मंत्री गणेश नाईक दूरदृश्य प्रणाली के माध्यम से शामिल हुए। वन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास रेड्डी, मंडल के सदस्य एवं मित्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

रानभैसों के संरक्षण पर जोर
गढ़चिरोली जिले का कोलामार्का क्षेत्र रानभैसों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तानसा वन्यजीव अभयारण्य को मानव-विहीन बनाने की योजना के तहत ओगदा, खोडदे, तिरमाल, पाचघर, फणसाड और आमले गांवों की 588.767 हेक्टेयर राज्य एवं निजी भूमि को नए विस्तारित तानसा वन्यजीव अभयारण्य में शामिल करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।

सात जिलों के 14 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र मंजूर

बैठक में जिन 14 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव मंडल की बैठक, रानभैसों के संरक्षण के लिए कोलामार्का को अभयारण्य बनाने का निर्णय



प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, उनमें पुणे और रायगढ़ जिलों का वेल्हे-मुलशी, पुणे का भोरगिरीगढ़, नासिक के दिंडोरी, सुरगना और ताहराबाद, नंदुरबार का चिंचभाड़ा, रायगढ़ के अलीबाग और चेरा मानिकगढ़, पुणे-रायगढ़ का लोनावला, ठाणे का गुमतारा, पालघर के जव्हार, आशेरीगढ़ और धामणी तथा चंद्रपुर का एकारा शामिल हैं। इसके अलावा कोका वन्यजीव अभयारण्य के 100.139 वर्ग किलोमीटर और जायकवाड़ी पक्षी वन्यजीव अभयारण्य के 255.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को संकटग्रस्त वन्यजीव आवास घोषित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

बांधों की मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं पर निर्देश
मुख्यमंत्री फडणवीस ने निर्देश दिया कि अभयारण्यों में बांधों की मरम्मत, पुनर्वास और गाद निकालने जैसे नियमित कार्य संबंधित प्रबंधन योजनाओं में शामिल किए जाएं। नियमों के अनुरूप मानक कार्यप्रणाली तैयार कर तीन महीने के भीतर प्रबंधन योजनाओं में जरूरी बदलाव किए जाएं। इन कार्यों के लिए हर बार अलग मंजूरी लेने के बजाय संबंधित वन्यजीव अधिकारियों को पूर्व सूचना देने की व्यवस्था

की जाए। बैठक में संरक्षित क्षेत्रों, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों और बाघ गलियारों में सिंचाई, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, पुल, सड़क, भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर और बिजली लाइनों सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

मानव-वन्यजीव संघर्ष और पुनर्वास पर चर्चा
राज्य के छह बाघ परियोजना क्षेत्रों के कोर, बफर और अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों को शांत क्षेत्र घोषित करने, मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा का दर्जा देने तथा बाघ परियोजनाओं के बफर क्षेत्रों में इच्छुक गांवों के पुनर्वास के लिए नीति बनाने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी, मौजूदा मुआवजा व्यवस्था और वन विभाग के अधिकारों के बीच तालमेल की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जिन क्षेत्रों को पहले ही अभयारण्य घोषित किया जा चुका है, लेकिन जो अब तक क्षेत्रीय वन विभाग या वन विकास निगम के प्रबंधन में हैं, उन्हें वन्यजीव शाखा को सौंपने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।

ई-चालान से नहीं, जुर्माना लगाने के तरीके से परेशानी: राज ठाकरे

नवी मुंबई में परिवहन कर्मचारियों की सभा में MNS प्रमुख ने शहरी नियोजन और ट्रैफिक प्रबंधन पर उठाए सवाल



मुद्दा उठाया। सभा के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वह पहले भी कई बार ट्रैफिक जाम की समस्या पर चिंता जता चुके हैं। उनके मुताबिक, मौजूदा हालात को देखते हुए भविष्य में यातायात को नियंत्रित करना और मुश्किल हो सकता है।

लोकल ट्रेन बंद हुई तो सड़कों पर क्या होगा ?

मुंबई की लोकल ट्रेन सेवाओं का उल्लेख करते हुए ठाकरे ने सवाल किया कि यदि किसी दिन लोकल ट्रेनें बंद हो जाएं और यात्रियों को निजी वाहनों से सफर करना पड़े, तो शहर की सड़कें इतनी अतिरिक्त यातायात कैसे संभालेंगी। उन्होंने मुंबई की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर आसपास के इलाकों में यातायात पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने वाहनों की बढ़ती संख्या और अनपेक्षित योजना के कारण सड़कों के साथ-साथ पुलिस पर भी बढ़ते दबाव का

उन्होंने अपने ड्राइवर्स को निर्देश दिया है कि जल्दबाजी या पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद ट्रैफिक सिग्नल न तोड़ें।
GDP के आंकड़ों से पहले बुनियादी समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत
MNS प्रमुख ने शहरी प्रबंधन की समस्याओं के बीच आर्थिक विकास के आंकड़ों पर दिए जा रहे जोर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब परिवहन और नियोजन से जुड़ी बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो केवल GDP वृद्धि के आंकड़ों का उल्लेख करने से आम नागरिकों को क्या लाभ होगा। ठाकरे ने वाहनों के पंजीकरण, जनसंख्या वृद्धि और शहरों में बढ़ती आबादी से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि इन समस्याओं का पूरा बोझ पुलिस पर नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि ट्रैफिक अनुशासन और प्रशासनिक कमियों को दूर करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी है।

Chandrababu Naidu Directs Officials to Prepare for Heavy Rains

AMARAVATI: Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu on Monday directed officials in coastal districts to take precautionary measures to prevent loss of life and property following an India Meteorological Department (IMD) warning of a possible severe cyclonic storm affecting the state. Officials informed the Chief Minister that the system was likely to cross the coast near Yanam, between Bapatla and Visakhapatnam, on October 28. Moderate to heavy rainfall was expected in several districts from Srikakulam to Nellore from Tuesday afternoon, accompanied by strong coastal winds. Heavy to extremely heavy rainfall was forecast for



October 28 and 29 in North Coastal Andhra, Konaseema, East Godavari, West Godavari, Eluru, Krishna, NTR, Guntur, Palnadu, Bapatla, Prakasam and Nellore districts. Naidu directed officials to keep the Central Government informed of the precautionary measures being taken. He ordered the relocation of people from flood-prone and low-lying areas to cyclone shelters, prioritising elderly persons, persons with disabilities, pregnant

women and infants. Officials said arrangements were being made to shift 4,711 identified pregnant women to primary health centres, community health centres and hospitals. The Chief Minister directed authorities to keep medical teams and ambulances ready in affected districts. He also ordered the deployment of seven National Disaster Response Force (NDRF) teams and eight State Disaster Response Force (SDRF) teams across 11 vulnerable districts. Additional teams were to remain on standby in NTR and Visakhapatnam districts. Officials were instructed to coordinate with the Marine Police, Navy and Coast Guard for rescue and relief operations.

Authorities reported that all fishermen who had ventured into the sea had returned safely, with 30,043 boats reaching harbours. Naidu directed officials to ensure that fishermen did not venture into the sea until the system weakened and conditions returned to normal. The Chief Minister instructed the Agriculture Department to move harvested paddy to safe locations and take measures to protect horticultural crops spread across approximately 1.82 lakh hectares. He also directed officials to maintain adequate stocks of essential commodities at ration shops and restore electricity supply promptly wherever disruptions occurred.

Pinarayi Vijayan, Family Get Relief in CMRL-Exalogic Case

KOCHI: The Kerala High Court's division bench stayed a single bench order directing registration of an FIR and an investigation into the CMRL-Exalogic case based on a letter from the Enforcement Directorate (ED). The bench halted further proceedings arising from the FIR and ordered suspension of the investigation while admitting appeals filed by Opposition Leader Pinarayi Vijayan, his daughter T. Veena, her husband and former minister P.A. Mohammed Riyas, and others. Issuing notices to the ED and state Vigilance, the court directed both agencies to submit detailed counter-affidavits within four weeks. Detailed hearings on the appeals will begin on November 25. During the proceedings,



the bench sharply criticised petitioner K.M. Shajahan, warning him against attempting to challenge a Supreme Court order before the High Court. When he said he intended to seek revision of the apex court's order, the bench responded that he should first get that order set aside. The court observed that support from the media or the public could not determine judicial proceedings. It also questioned whether Shajahan had followed the prescribed procedure for pursuing a criminal complaint. Ex-

plaining the sequence, the bench said a complainant should first approach police, then a superior officer if no action followed, and subsequently the magistrate, who could refer the complaint to police. Shajahan replied that he could not directly approach the magistrate in this matter and had complained to the state police chief. Vijayan and Veena had challenged the single bench ruling, contending that it was issued without hearing them. After the division bench initially rejected their appeals, they approached the Supreme Court along with Riyas. The apex court stayed the single bench order for a week and directed the High Court's division bench to reconsider and decide their appeals.

Delhi to Get New Tourism Attraction with Yamuna River Safari

NEW DELHI: Delhi Chief Minister Rekha Gupta on Monday inspected the trial run of the 'Namo Yamuna River Safari', a cruise service being developed along the Yamuna River between Sonia Vihar and Jagatpur. During the visit, she received a detailed briefing from officials on the project's progress, operational arrangements and facilities being developed for passengers. The Chief Minister said the people of Delhi shared a deep emotional and cultural bond with the Yamuna. The introduction of the river safari, she said, would give

this connection a new dimension while opening up fresh avenues for tourism and recreation in the national capital. CM Gupta said the government planned to formally launch the service before the Chhath festival so that residents could experience the new attraction. The initiative would allow people to enjoy a cruise while viewing the Yamuna and would mark an important step towards developing an appealing tourism destination for families. She emphasised that while tourism infrastructure was being developed, equal importance must



be given to maintaining the river's cleanliness and protecting the environment. Delhi Tourism Minister Kapil Mishra and officials from the departments concerned were also present during the inspection. The Chief Minister

said the cruise service was being developed along an approximately six-kilometre stretch of the river between Sonia Vihar and Jagatpur. The project is expected to open up new tourism opportunities in Delhi, stimulate local economic activity and generate employment. Facilities along the riverfront are being developed to transform the area into an attractive destination for tourism and recreation. As part of the project, facilities for visitors will include food kiosks, restaurants, a children's play zone and other essential

public amenities. During the inspection, officials informed the Chief Minister that preparations were under way to operate a cruise with a capacity of 30 passengers on the route. The round trip from Sonia Vihar to the Shani Temple at Jagatpur and back is expected to take approximately 35 to 45 minutes. Passengers will enjoy a boat ride along the designated route before returning to their point of departure. The trial run is planned to continue for approximately one week, with the formal inauguration tentatively scheduled for

the first week of November. An official announcement will be made once the final date has been decided. Under the proposed pricing structure, visitors will be charged an entry fee of Rs. 50 for the premises, while the proposed fare for a complete cruise journey will be Rs. 500. CM Gupta appreciated the efforts of the concerned departments of the Central and Delhi governments in bringing the project to fruition. She said effective coordination among various agencies was helping create new tourism opportunities in the capital.

गुजरातः भारत-पाकिस्तान सीमेजवळ 4 पाकिस्तानी मासेमारांना अटक

कच्छ: भारत-पाकिस्तान सीमेजवळील गुजरातच्या कच्छ जिल्ह्यात सीमा सुरक्षा दलाने (बीएसएफ) कारवाई करत 4 पाकिस्तानी मच्छीमारांना ताब्यात घेतले. रविवारी सर क्रीक परिसरातील दलदलीच्या भागात खेकडे पकडण्याच्या बहाण्याने हे मच्छीमार भारतीय जलक्षेत्रात दाखल झाल्याची माहिती आहे. या कारवाईदरम्यान बीएसएफने त्यांची मासेमारीची नौकाही जप्त केली. गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ही विशेष मोहीम राबवण्यात आली. बीएसएफच्या माहितीनुसार, ताब्यात घेतलेल्या मच्छीमारांची नावे कादिर थेमोर, मुहम्मद मूसा, असगर थेमोर आणि अहसान जट अशी आहेत. हे चौघेही पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील 'चाच जान खान' गावाचे रहिवासी आहेत. त्यांची सुरक्षा यंत्रणांकडून पुढील चौकशी सुरू आहे. सर क्रीक हा कच्छच्या रणगीतल गुजरात आणि पाकिस्तानच्या सिंध प्रांताच्या किनारपट्टीदरम्यान असलेला अरुंद, भरती-ओहोटीच्या प्रभावाखालील खाडीचा भाग आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील



दीर्घकालीन सीमावादाच्या दृष्टीने हा परिसर अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. या वादाचा संबंध अरबी समुद्रातील सागरी सीमारेषेच्या निर्धारणाशीही आहे. या परिसरातील उथळ पाणी, भरती-ओहोटी आणि विस्तीर्ण दलदलीचा प्रदेश यांमुळे नौकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे तसेच सीमारेषेची निगराणी करणे सुरक्षा यंत्रणांसाठी आव्हानात्मक ठरते. मासेमारीदरम्यान काही मच्छीमार नकळत, तर काही जाणीवपूर्वक सीमारेषा ओलांडत असल्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे या भागातील सुरक्षा व्यवस्थेला विशेष महत्त्व आहे. भारताच्या पश्चिम सीमेवरील या संवेदनशील भागात बीएसएफकडून नियमित गस्त आणि देखरेख ठेवली जाते. अनधिकृत सीमा ओलांडणे तसेच इतर बेकायदा हालचाली रोखण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा सतर्क आहेत.

अयोध्येतून 4 डिसेंबरपासून परशुराम कुंडपर्यंत निमंत्रण रथयात्रा होणार रवाना

कोलकाता: अरुणाचल प्रदेशातील 'श्री परशुराम कुंड' येथे उभारण्यात आलेल्या भगवान परशुरामांच्या ५१ फूट उंच पुतळ्याच्या अनावरण सोहळ्याची तयारी वेगवान करण्यासाठी, 'विप्र फाऊंडेशन'तर्फे देशभर एक 'निमंत्रण रथयात्रा' आयोजित केली जाणार आहे. ही रथयात्रा ४ डिसेंबर २०२६ रोजी अयोध्येतून सुरू होईल आणि २४ डिसेंबर २०२६ रोजी श्री परशुराम कुंड येथे पोहोचेल. या उपक्रमाद्वारे, जानेवारी-फेब्रुवारी २०२७ मध्ये प्रस्तावित असलेल्या पुतळ्याच्या अनावरण सोहळ्यासाठी देशभरातील भाविकांना निमंत्रित केले जाईल. सोहळ्याची निश्चित तारीख संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर जाहीर केली जाईल. या रथयात्रेच्या आणि अनावरण सोहळ्याच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यासाठी, रविवारी कोलकाता येथील ई.एम. बायपासवरील 'सिंग क्लब'मध्ये विप्र फाऊंडेशनच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीची एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यनारायण श्रीमाली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत देशभरातील १५० हून अधिक पदाधिकारी, कार्यकारी सदस्य आणि विशेष निमंत्रित व्यक्ती उपस्थित होत्या; त्यापैकी १४७ प्रतिनिधींनी उपस्थिती नोंदवली. ही बैठक ऑनलाइन माध्यमातूनही प्रसारित करण्यात आली होती. बैठकीचे कामकाज संस्थेचे सरचिटणीस डॉ. सुनील शर्मा यांनी पाहिले. यावेळी संस्थेचे संस्थापक सुशील ओझा, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवारीलाल सोती, धर्मनारायण जोशी आणि राधेश्याम शर्मा 'गुरुजी' यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच, 'विप्र चेंबर ऑफ



कॉमर्स अँड इंडस्ट्री'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विजय बसोटीया आणि 'इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर परशुराम कॉन्सर्नेस'च्या अध्यक्षा डॉ. हर्षा त्रिवेदी यांचीही उपस्थिती होती. ही बैठक विप्र फाऊंडेशनच्या 'झोन-७' (कोलकाता) द्वारे, विभागीय अध्यक्ष किशन गोस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आली होती. दोन समित्यांची स्थापना आणि पुनर्रचना करण्याबाबत निर्णय बैठकीदरम्यान 'परशुराम मूर्ती स्थापना समिती'ची पुनर्रचना करण्यात आली. यामध्ये धर्मनारायण जोशी यांची चेअरमन, परमेश्वर शर्मा यांची अध्यक्ष म्हणून आणि रमेश शर्मा यांची संयोजक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या समितीमध्ये इतर आठ पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त, संस्थेची कामे आणि उपक्रमांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एका 'उच्चस्तरीय शिस्तपालन समिती'ची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या अध्यक्षापदी राधेश्याम शर्मा, तर संयोजकपदी श्रीकांत पराशर यांची नियुक्ती करण्यात आली.

कानडींना डावलल्यास आयटी कंपन्यांवर कठोर कारवाई : डी. के. शिवकुमार

बेंगळूरु: कर्नाटातील आयटी कंपन्यांकडून नोकरीच्या संधी देताना कन्नड भाषिक उमेदवारांना जाणीवपूर्वक डावलले जात असल्याचे आव्हान कन्नड भाषिकांचे हक्क, सन्मान आणि रोजगाराच्या संधीकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवकुमार यांनी रविवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत या प्रकरणाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतल्याचे सांगितले. बेंगळूरूमधील आयटी कंपन्यांमध्ये कन्नड भाषिकांना नोकरीच्या संधींपासून वंचित ठेवले जात असल्याचे ऐकून दुःख होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्थानिक उमेदवारांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. बेंगळूरू हे जागतिक स्तरावरील महत्त्वाचे तंत्रज्ञान केंद्र असून, राज्यातील स्थानिक मनुष्यबळाची क्षमता आणि गुणवत्ता यांचा सरकारला



अभिमान आहे, असे शिवकुमार यांनी म्हटले. मात्र, कन्नड भाषिक उमेदवारांशी जाणीवपूर्वक भेदभाव करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध सरकार आवश्यक ती कारवाई करू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला. कन्नड भाषिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि त्यांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहील, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, सोशल मीडियावर एका तरुणीचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. या व्हिडीओमध्ये संबंधित तरुणीने आयटी कंपन्यांमधील भरती प्रक्रियेत कन्नड भाषिक उमेदवारांशी भेदभाव होत असल्याचा आरोप केला आहे. तेलुगू आणि तमिळ भाषिक उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाते, तर अर्जदाराच्या बायोडेटामध्ये कन्नड भाषेचा उल्लेख असल्यास त्याचा अर्ज कथितरीत्या नाकारला जातो, असा दावा तिने केला आहे.

झोन हल्ल्यांमध्ये स्टारलिनकचा गैरवापर, युक्रेनवर इलॉन मस्क यांचा आरोप

वॉशिंग्टन: अब्जाधीश उद्योगपती इलॉन मस्क यांनी युक्रेनवर स्टारलिनकच्या सेवाशक्तीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. मस्क यांचा दावा आहे की युक्रेनने लोकांना मारण्यासाठी झोन हल्ल्यांमध्ये त्याचा वापर केला. स्पेसएक्सने तयार केलेल्या आणि युक्रेनच्या लष्करी कारवायांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या या नेटवर्कवरून वॉशिंग्टन आणि कीव यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा आरोप करण्यात आला आहे. मस्क यांनी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये लिहिले,

युक्रेनच्या लष्कराने स्टारलिनकच्या सेवाशक्तीचे उल्लंघन केले आणि लोकांना मारण्यासाठी आक्रमक झोन हल्ल्यांमध्ये त्याचा वापर केला. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, ही त्रुटी गेल्या आठवड्यात दूर करण्यात आली होती. दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले, स्टारलिनकच्या अटींमध्ये नेहमीच ती एक नागरी प्रणाली म्हणून परिभाषित केली गेली आहे, लोकांना मारण्याचे साधन म्हणून नाही. या अटींचे उल्लंघन केल्यास सेवा बंद केली जाईल. इलॉन मस्क यांनी म्हटले आहे की स्टारलिनक युक्रेनच्या सुरक्षेसाठी



अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण ही एकमेव प्रणाली आहे जिला जाम किंवा नष्ट केले जाऊ शकत नाही. जर स्टारलिनक

बंद झाली, तर युक्रेनच्या आघाडीच्या रेषा तात्काळ कोसळतील. २०२२ मध्ये रशियाने केलेल्या आक्रमणापासून मस्कने युक्रेनबाबत आपली भूमिका अनेक वेळा बदलली असली तरी, कोणत्याही सेवा व्यत्ययासाठी स्पेसएक्स नव्हे, तर अमेरिकन सरकार जबाबदार आहे, असे त्यांनी नेहमीच म्हटले आहे. रशियाच्या क्षेपाणास्त्र आणि झोन हल्ल्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी युक्रेन नागरी स्टारलिनक उपग्रह दळणवळण प्रणाली आणि तिची लष्करी आवृत्ती, स्टारशील्ड, यावर अवलंबून आहे. संरक्षण मंत्री

येवेगेनी खमारा यांनी एका निवेदनात म्हटले, मॉनिटरिंग प्रणाली दर्शवते की स्टारलिनक/स्टारशील्डचा वेग सुधारला आहे. आम्ही आता ताशी ४०० किमी पेक्षा जास्त वेग गाठत आहोत आणि कनेक्शन स्थिर आहे. हा परिणाम आमच्या आघाडीच्या फळीसाठी, आमच्या सैन्यासाठी, झोन ऑपरेशन्ससाठी, लॉजिस्टिक्ससाठी आणि दळणवळण प्रणालींसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, सध्या आम्हाला या वेगाची गरज आहे. रात्रीतून सेवा पूर्ववत होण्यास सुरुवात झाली.

त्यांनी जोर देऊन सांगितले, हे खूप महत्त्वाचे आहे, आमच्या आघाडीच्या लॉजिस्टिक्ससाठी आणि रॉकेट-चालित झोनपासून युक्रेनच्या संरक्षणासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे. हे उपग्रह नेटवर्क युक्रेन आणि अमेरिका यांच्यातील वादाचे केंद्र बनले आहे. झेलेन्स्की यांनी अमेरिकेवर रशियाला मदत केल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, वॉशिंग्टनने कीवला आगामी क्षेपाणास्त्र हल्ल्यांबद्दल सावध करण्यात अपयश आले आणि स्टारलिनकचा वेग कमी करून त्यांच्या लष्करी प्रतिसादाला कमकुवत केले.

अहान पांडे-शरवरी की फिल्म 'बेपरवाह' का ऐलान

यशराज फिल्म ने अपनी आगामी रोमांटिक एक्शन-ड्रामा फिल्म के शीर्षक की घोषणा कर दी है। अहान पांडे और शरवरी अभिनीत इस फिल्म का नाम 'बेपरवाह' रखा गया है। फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर कर रहे हैं, जबकि आदित्य चोपड़ा इसके निर्माता हैं। निर्माताओं ने फिल्म के नाम के साथ इसका टीजर पोस्टर भी जारी किया है। यह घोषणा फिल्म की सिनेमाघरों में रिलीज से ठीक पांच महीने पहले की गई है। 'बेपरवाह' के जरिए अहान



पांडे और शरवरी पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। अहान पांडे ने फिल्म 'सैयारा' से दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई थी। अब वह शरवरी के साथ एक रोमांटिक एक्शन-ड्रामा में

दिखाई देंगे। फिल्म के शीर्षक और टीजर पोस्टर की घोषणा के बाद दर्शकों को इसकी कहानी और दोनों कलाकारों की जोड़ी को लेकर उत्सुकता रहेगी। हालांकि, निर्माताओं ने फिलहाल फिल्म की कहानी से

जुड़ी विस्तृत जानकारी शेर नहीं की है। निर्देशक अली अब्बास जफर की यशराज फिल्म के साथ यह वापसी है। इससे पहले वह इस प्रोडक्शन हाउस के लिए 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। दोनों फिल्मों को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। ऐसे में 'बेपरवाह' में भी रोमांस और एक्शन का मेल देखने को मिलेगा। आदित्य चोपड़ा के निर्माण में बन रही यह फिल्म 26 मार्च, 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'द इंडिया हाउस' से सई एम. मांजरेकर का पहला लुक आया समाने

अभिनेता राम चरण के निर्माण में बन रही पीरियड ड्रामा फिल्म 'द इंडिया हाउस' से अभिनेत्री सई एम. मांजरेकर का पहला लुक सामने आया है। आजादी से पहले के दौर पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों एस्टोनिया में चल रही है। जारी तस्वीर में सई एक अलग और प्रभावशाली अंदाज में नजर आ रही हैं। उनके इस लुक ने फिल्म में उनके किरदार को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। तस्वीर में सई सफेद रंग के पूरी बांहों वाले ब्लाउज और मैरून रंग की लंबी स्कर्ट में दिखाई दे रही हैं। इसके साथ उन्होंने गहरे



रंग की स्टॉकिंग्स और सफेद जूते पहने हैं। खुले बालों और हाथ में जलती मशाल के साथ उनका अंदाज दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। उनके पीछे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा एक बैनर भी दिखाई दे रहा है। इस झलक से संकेत मिलता है कि फिल्म में उनका किरदार

अपने विचारों और उद्देश्य के लिए मजबूती से खड़ा नजर आ सकता है। हालांकि, निर्माताओं ने उनके किरदार से जुड़ी विस्तृत जानकारी शेर नहीं की है। 'द इंडिया हाउस' में सई का यह रूप उनके पहले के किरदारों से अलग दिखाई देता है। फिल्म

से जुड़े एक करीबी सूत्र के अनुसार, अभिनेत्री का किरदार कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उनका लुक उस दौर के माहौल और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सूत्र ने बताया कि फिल्म में दर्शकों को सई के अभिनय का एक नया रूप देखने को मिलेगा। राम चरण द्वारा निर्मित यह फिल्म ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण दौर की कहानी पेश करेगी। अब दर्शकों को फिल्म में सई के किरदार और उसकी भूमिका के बारे में अधिक जानकारी सामने आने का इंतजार है।

ट्रोलिंग पर रश्मिका का जवाब, विजय के लिए जताया प्यार

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं। 'कॉफी विद करण' के दूसरे एपिसोड में नजर आने के बाद दोनों सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं। विजय को लेकर जहां कुछ यूजर्स ने नकारात्मक टिप्पणियां कीं, वहीं रश्मिका को उन्हें 100 बार प्रपोज करने की बात पर निशाना

बनाया गया। अब अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेर कर ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वह विजय को 100 नहीं, बल्कि 1000 बार प्रपोज करने के लिए तैयार हैं। रश्मिका ने अपनी पोस्ट में लिखा कि इंटरनेट पर चल रही बहस उन्हें ऐसी गुस्साईं भीड़ जैसी लगती है, जो अपना गुस्सा निकालने के



लिए किसी व्यक्ति को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की प्रतिक्रियाओं ने उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। अभिनेत्री के मुताबिक, उनके और विजय के लिए प्रपोज की संख्या या किसी भव्य आयोजन से ज्यादा जरूरी एक-दूसरे को समझने के लिए समय लेना था। उन्होंने विजय को सोच-समझकर फैसले लेने

वाला व्यक्ति बताया और कहा कि दोनों एक-दूसरे की जिंदगी में जरूरी संतुलन लेकर आते हैं। रश्मिका ने अपने रिश्ते का बचाव करते हुए कहा कि शादी का मतलब उनके लिए साथ मिलकर जीवन और भविष्य बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने पार्टनर को लेकर बेहद भावुक हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। अभिनेत्री ने बताया

कि मुश्किल समय में विजय उनके साथ खड़े रहे, जबकि उस वक्त सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में लोग मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि वह आज बेहद खुश हैं और उनकी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई देती है। साथ ही, रश्मिका ने प्रशंसकों का आभार जताते हुए अपने परिवार को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए।

रोजाना पैदल चलने से किशोरों की मानसिक सेहत बेहतर

किशोरावस्था दिमाग के विकास और मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से जीवन का बेहद अहम दौर होता है। इस उम्र में शारीरिक गतिविधियां न केवल शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं, बल्कि दिमागी विकास और भावनात्मक संतुलन पर भी सकारात्मक असर डाल सकती हैं। हाल ही में किशोरों पर किए गए एक दिलचस्प शोध में सामने आया है कि पैदल चलने जैसी आसान शारीरिक गतिविधि भी लंबे समय में काफी फायदेमंद हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक, किशोर रोजाना जितना ज्यादा पैदल चलते हैं, ठीक एक साल बाद उनमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं उतनी ही कम पाई जाती हैं। यह अध्ययन बताता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में चलने-फिरने की आदत को बढ़ावा देकर किशोरों की शारीरिक और मानसिक सेहत को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

12,000 कदमों का कमाल
अध्ययन में पाया गया है कि जो किशोर दिन भर में 12,000 या उससे ज्यादा कदम चलते हैं, उनके व्यवहार और भावनाओं से जुड़ी परेशानियां सबसे कम होती हैं। कदमों की संख्या और बेहतर



मानसिक सेहत के बीच का यह सीधा कनेक्शन वाकई हैरान करने वाला है।

दिमाग की बनावट में दिखा बदलाव

'जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन नेटवर्क ओपन' में प्रकाशित इस रिसर्च के निष्कर्षों की पुष्टि न्यूरोइमेजिंग के जरिए भी हुई है। स्कैन में सामने आया कि जिन किशोरों ने सबसे ज्यादा कदम चले, उनके दिमाग के उन खास हिस्सों में 'कार्टिकल टिश्यू' ज्यादा मोटे पाए गए, जो इंसान के मूवमेंट और भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट में काइनेसियोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर अर्मांडा पालुच के अनुसार,

यह देखना बहुत ही उत्साहजनक है कि शारीरिक गतिविधि से दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को सीधा फायदा पहुंचता है। उन्होंने साफ किया कि यह स्थिति 'सब या कुछ नहीं' वाली नहीं है। यानी, इन फायदों को पाने के लिए किशोरों का बेहतरीन एथलीट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर कोई किशोर रोजाना चलने वाले अपने कदमों में केवल 1,000 से 2,000 कदम और जोड़ लेता है, तो भी उसके दिमाग की बनावट और मानसिक स्वास्थ्य में काफी बेहतर नतीजे देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कदमों की संख्या के साथ-साथ यह फायदेमंद असर आगे भी लगातार बढ़ता रहता है।

बिगड़ता लाइफस्टाइल बढ़ा सकता है डायबिटीज का खतरा

डायबिटीज आज के समय में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, जो आने वाले वर्षों में लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। बदलती जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें और शारीरिक गतिविधियों की कमी इस बीमारी के जोखिम को बढ़ाने वाले प्रमुख कारकों में शामिल हैं। भारत में भी डायबिटीज के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई जाती रही है। खासकर टाइप-2 डायबिटीज का खतरा उन लोगों में अधिक हो सकता है, जिनकी दिनचर्या में असंतुलित आहार, पर्याप्त नींद की कमी और लंबे समय तक बैठे रहने जैसी आदतें शामिल हैं। अक्सर लोग रोजमर्रा की इन आदतों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लंबे समय में इनका असर सेहत पर पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते अपनी जीवनशैली पर ध्यान दिया जाए। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ आम आदतों के बारे में, जो टाइप-2 डायबिटीज के जोखिम को बढ़ा सकती हैं और जिन्हें बदलकर बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है।

पैकेट फूड ज्यादा खाना

पैकेट फूड का ज्यादा सेवन टाइप-2 डायबिटीज के साथ-साथ डिप्रेशन और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। नेशनल लाइव्री ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर



आप 10% पैकेट प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन बढ़ाते हैं, तो उससे 15% डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है।

सुबह का नाश्ता न करना

साल 2019 में द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक स्टडी कहती है कि जो लोग ज्यादातर समय अपना रोज का नाश्ता जल्दबाजी में छोड़ देते हैं, उनमें आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाश्ता न करने से हमारे शरीर की सेल्स इंसुलिन हार्मोन को लेकर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करती।

एक जगह 30 मिनट से ज्यादा बैठना

डॉक्टर यूं ही रोजाना एक्सरसाइज करने की सलाह नहीं देते, क्योंकि एक जगह लंबे समय तक बैठे रहना और शरीर को एक्टिव न रखना सीधे तौर पर टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ाता है। जबकि आज के कॉर्पोरेट कल्चर में लैपटॉप और कंप्यूटर के

सामने बैठना लोगों में आदत बन गई है, जिसे समय रहते सुधारने में भलाई है।

नींद पूरी न लेना

नींद और टाइप 2 डायबिटीज के बीच कनेक्शन के बारे में साल 2022 में डायबिटीज केयर जर्नल में प्रकाशित हुआ था। करीब 3 लाख लोगों पर हुई स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों को सोने में परेशानी होती है या उनका स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ है, उनमें डायबिटीज का जोखिम भी ज्यादा रहता है।

स्मॉकिंग

सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो स्मॉकिंग करने वालों को बाकी लोगों की तुलना में डायबिटीज का 30-40% ज्यादा खतरा रहता है। हालांकि, एक्सपर्ट्स ने इसे लेकर अभी तक कोई सीधा संबंध नहीं पाया है, लेकिन स्मॉकिंग का तनाव से लिंक बताया गया है।

युवाओं पर बढ़ता दबाव, मानसिक सेहत के प्रति जागरूकता जरूरी

रोजमर्रा के जीवन में होने वाले तनाव को संगीत, यात्रा अथवा प्राणायाम से ठीक कर लेना चाहते हैं तो ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। वास्तव में मानसिक सेहत को लेकर यही धारणा रही है। हालांकि, समय के साथ जागरूकता बढ़ी है, पर इसे संपूर्ण सेहत का अंग मानना जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि मन भी शरीर की तरह बीमार होता है। यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो थकान व सुस्ती होती है, किसी से बात करना का भी मन नहीं करता। लोग आपसे इस बदले व्यवहार का कारण पूछते हैं। इसी तरह हीमोग्लोबिन कम होने का प्रभाव आपके शरीर व मन पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों पर भी पड़ता है। एम्स दिल्ली के वरिष्ठ मनोचिकित्सक कहते हैं, यदि आप किसी बात से परेशान हैं, कुछ सूझ नहीं रहा है कि आपको उस समय क्या करना चाहिए तो इसके लिए स्वयं को दोषी मानने के बजाय बाहरी कारणों को समझें। यह कुछ भी हो सकता है। हर बात का आपके मन पर असर पड़ता है। समस्या

अधिक बढ़े इससे पहले चेतना जरूरी है अन्यथा यह गंभीर व जानलेवा रूप ले सकती है। इस समय देश में बड़ी संख्या में युवाओं में अवसाद के मामले सामने आए हैं। आत्महत्या की खबरें आए दिन स्तब्ध कर रही हैं। भारतीय मनोचिकित्सा सोसाइटी के अनुसार, देश में कुल मानसिक विकारों के मामलों में से लगभग 60 प्रतिशत मामले 35 वर्ष से कम उम्र के युवाओं और किशोरों से जुड़े हैं।

सफलता और मानसिक सेहत

बीते दिनों आईआईटी जैसे देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में होने वाली आत्महत्याएं बताती हैं कि मानसिक सेहत का असाधारण प्रतिभा, शिक्षा या सफलता से विशेष सरोकार नहीं है। डॉक्टरों की आत्महत्या की खबरें तो सुनी तो कई लोगों को हैरानी हुई। इतिहास के सबसे सफल ओलंपियन तैराक माइकल फेलप्स ने भी अवसाद का सामना किया है, वह उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा है। वर्ष 2021 में जिम्मास्ट सिमोन बाइल्स ने भी अपनी



खराब मानसिक सेहत के लिए ओलंपिक प्रतियोगिता से अपना नाम वापस लिया। प्रोफेसर के अनुसार, 15-30 साल के युवा इस समय सबसे अधिक तनाव में हैं। जब वे आईआईटी जैसे संस्थानों में जाते हैं तो वहां परीक्षा पास कर लक्ष्य पूरा करने का तनाव कम नहीं होता। वह एक ऐसे परिवेश में प्रवेश करते हैं जहां उनका तनाव और बढ़ जाता है। वहां रहते दिमाग एक ही दिशा में काम कर रहा होता है कि कैसे अपनी श्रेष्ठता को बरकरार रखा जाए। लोगों से मिलना जुलना या परिवार समाज से कोई खास मतलब नहीं होता, बस नजर रहती है कि कुछ बड़ा प्राप्त करने पर। उच्च शिक्षण

संस्थानों में रहने वाले बच्चों को बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है कि जब कुछ बन जाओगे तो लोग तुम्हारी सुनेंगे, पर जब यह नहीं होता तो उनमें असंतोष पैदा होता है। वे खुद को कम आंकते हैं जबकि यह सीख व्यावहारिक नहीं है। चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। चुनौतियों से जूझकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। वहां रहकर भी जिन बच्चों का परिवार-समाज से भी जुड़ाव रहता है वे अपेक्षाकृत अधिक बेहतर तालमेल बना पाते हैं। प्रतिभाशाली छात्रों या लोगों में आत्महत्या की घटनाएं एक दिन में नहीं होती, यह एक प्रक्रिया है जो धीरे-धीरे उन्हें एक दिन ऐसा करने पर बाध्य कर देती हैं। जब उन्हें लगता है कि अपनी परेशानी से निकलने के लिए यही एकमात्र राह बची है, अब उन्हें कोई सुनेगा नहीं, कोई मदद नहीं करेगा।

मास्क डिप्रेशन तो नहीं ?

सफलता या मानसिक सेहत एक-दूसरे की विरोधी तो नहीं, पर सफल लोग बीमार नहीं हो सकते यह कहना उनके ऊपर अतिरिक्त

दबाव डालना है। यह एक बड़ा कारण है कि ऐसे लोग मास्क डिप्रेशन में जीने लगते हैं। बाहर से मुस्कुराते रहना, सब ठीक है ऐसी भाव-भंगिमा को बनाए रखना ताकि लोग समझ न पाएं कि वे अपनी परेशानियों से उबर नहीं पा रहे। दरअसल, अवसाद या तनाव से जूझ रहे लोगों की छवि अक्सर उदास या सामाजिक संपर्क से कटे व्यक्ति की बनी रहती है। वे खुद इस छवि से बाहर नहीं आना चाहते। वास्तव में अवसाद से पीड़ित लोग भी उच्च कार्यक्षमता व सामाजिक रूप से सक्रिय दिखायी पड़ सकते हैं। उनके रिश्ते भी अच्छे हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि अवसाद को किसी खास लक्षणों के दायरे में बांधने के बजाय विशेषज्ञों से परामर्श लेकर ही समझें।

लक्षणों को समझें

- अधिकांश समय में उदासी या निराशा महसूस होना।
- छोटी-छोटी बातों का गुस्सा, झुंझलाहट या भावनात्मक उबाल आना।

- नींद नहीं आने या बहुत आने जैसी समस्या। भूख में बढ़ोत्तरी या कमी।
- पसंदीदा काम में अरुचि होना, पारिवारिक गतिविधियों से दूर रहना।
- ऊर्जा में कमी महसूस होना, सिरदर्द, एंजिडिटी या अन्य शारीरिक लक्षण।
- एकाग्रता में कमी आना, निर्णय लेने में कठिनाई।
- आत्मघाती विचार या स्वयं को दोषी मानना।
- छोटी मगर काम की बातें
- मानसिक सेहत के लिए लक्ष्य बनाएं। जैसे नींद पूरी करना, कोई समस्या हो तो मदद मांगना।
- आराम के लिए समय निकालना, ध्यान, कसरत और दोस्तों से मिलना-जुलना।
- परफेक्ट कोई नहीं यह ध्यान रहे, अवकाश लेना आवश्यक है।
- कोई समस्या है तो यह आपकी व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है बल्कि लक्षणों को पहचानकर समस्या दूर हो सकती है, यह स्वीकारें।

दोहरे हत्याकांड में ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह समेत आठ दोषी, क्रॉस केस में छह को सजा का इंतजार

संवाददाता
आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ग्राम पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर करीब 19 वर्ष पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड और उससे जुड़े क्रॉस केस में अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक, कमलापति की अदालत ने दोहरे हत्याकांड में ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह समेत आठ आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया। वहीं, क्रॉस केस में कातिलाना हमले और मारपीट के मामले में छह आरोपियों को दोषी पाया गया। दोनों मामलों में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 29 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रानी की सराय थाना क्षेत्र के रुदरी गांव निवासी रामजन्म सिंह 21 अक्टूबर 2007 को दशहरे के दिन सुबह करीब नौ बजे अपने दरवाजे पर बैठे थे। इसी दौरान तत्कालीन ग्राम प्रधान विपिन सिंह, राजेश सिंह, चुन्नु उर्फ रणविजय, बलवंत सिंह, राधेश्याम सिंह, छोटू उर्फ पंकज, लोकनाथ सिंह, जीवन प्रकाश और शिवादास सिंह हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे। आरोप था कि विपिन सिंह के ललकारने पर हमलावरों ने हमला कर दिया। इस दौरान दो सगे भाइयों तालुकदार सिंह और पारसनाथ



सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं, रामजन्म सिंह के भतीजे अंकित सिंह और आशीष को लाठी-डंडों से पीटा गया। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी राधेश्याम सिंह की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी की और कुल 17 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद अदालत ने आठ आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया। इस मामले में पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद अदालत ने छह आरोपियों को कातिलाना हमले और मारपीट का दोषी पाया। अब दोनों मामलों में दोषियों को सजा 29 अक्टूबर को सुनाई जाएगी।

टेसू-झांझी के मंगलगीतों के बीच मौत का तांडव तेज रफ्तार कार ने पांच लोगों को रौंदा

संवाददाता
फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। शिकोहाबाद क्षेत्र के छंटेनपुरा गांव में रविवार रात टेसू-झांझी की शादी के मंगलगीत गाते हुए विसर्जन के लिए निकली महिलाओं और ग्रामीणों की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब एक तेज रफ्तार कार ने उत्तव मना रहे लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। घायल चंद्रवीर के मुताबिक, कार सवार बटेश्वर की ओर से आते समय पहले लोगों को टक्कर मारकर भागने की कोशिश कर रहे थे। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर सड़क पर लगाकर उड़ रहे नकेले का प्रयास किया तो कार सवारों ने भागने के दौरान दोबारा भीड़ की ओर गाड़ी दौड़ा दी। इससे कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद कार सवार भी घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला संयुक्त अस्पताल, शिकोहाबाद पहुंचाया।
दो सगी बहनों की मौत से गांव में मातम
हादसे में मृत दो सगी बहनों आकांक्षा और अंजलि के शवों को रात करीब सवा दस बजे पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की तैयारी हुई तो ग्रामीणों ने निरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि घटना की सूचना देने के बावजूद पुलिस समय पर मौके पर



नहीं पहुंची। हंगामे की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और एसएसपी आदित्य लॉन्गे मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया, जिसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा सके।
अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना
हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इनमें डीएम संतोष कुमार शर्मा, एसएसपी आदित्य लॉन्गे, एसपी देहात अनुज चौधरी, सीओ सिरसागंज चंचल त्यागी, सीओ शिकोहाबाद जयबिंद गुप्ता, एसडीएम शिकोहाबाद राजेश शुक्ला, मखनपुर इस्पेक्टर चमन शर्मा और सिरसागंज इस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह शामिल रहे। अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। संवेदना

सपा में पूर्व आईएस समेत कई नेताओं की एंट्री अखिलेश बोले- आने वाले समय में जीत बड़ी होने जा रही है



लखनऊ में प्रेसवार्ता के दौरान पूर्व आईएस राम बहादुर पासी समेत कई नेताओं ने ग्रहण की सदस्यता, आउटसोर्सिंग खत्म करने और गरीबों को आवास देने का वादा
लखनऊ, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान विभिन्न दलों से आए नेताओं का स्वागत किया। पूर्व आईएस राम बहादुर पासी, कुशग्राम शास्त्र्य, विनोद शांकर्य और बसपा से जुड़े राम बहादुर पाल समेत कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अखिलेश यादव ने कहा कि नए नेताओं के पार्टी में शामिल होने से पूरे बसे पश्चिम तक राजनीतिक हलचल हुई है। उन्होंने नए साथियों को पीडीए का पिलर बताते हुए कहा कि आने वाले समय में जीत बड़ी होने जा रही है। दारा सिंह प्रजापति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा- जिनके साथ दारा होंगे, अखाड़ा वहीं जीतेगे। राम नाम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, "जिनके नाम में राम जुड़ा हो, उनके बन जाएंगे सब काम।"
आउटसोर्सिंग खत्म करने और गरीबों को आवास देने का वादा
अखिलेश यादव ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर अवकाश देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म की जाएगी और सफाई कर्मचारियों के हित में विशेष घोषणा की जाएगी। उन्होंने गरीब परिवारों को उनके घरों का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में काम करने तथा जिन गरीबों के पास घर नहीं हैं, उनके लिए अलग से आवास बनाकर देने की व्यवस्था करने की बात भी कही।
मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप, आधार से जोड़ने की मांग
सपा अध्यक्ष ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोटर लिस्ट में धांधली और वोट डकैती कर रही है। अखिलेश ने कहा, "जिनके नाम में राम जुड़ा हो, उनके बन जाएंगे सब काम।"

झांसी में 37 केंद्रों पर पीईटी-2026 की परीक्षा संपन्न, डीएम-एसएसपी ने किया निरीक्षण

देवेश प्रताप सिंह राठौर
झांसी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 रविवार, 25 अक्टूबर को झांसी जिले के 37 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की गई। जिलाधिकारी गौरांग राठी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने राजकीय इंटर कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने नकलविहीन और पारदर्शी परीक्षा संपन्न कराने के लिए केंद्र व्यवस्थापकों तथा सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को आवश्यक निर्देश दिए।
सीसीटीवी और बायोमैट्रिक व्यवस्था की जांच
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परीक्षार्थियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता और परीक्षा कक्षों की व्यवस्था की जांच की। जिलाधिकारी ने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, शौचालय और प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी सीसीटीवी कैमरों को लगातार चालू रखने के भी निर्देश दिए।
दोनों पालियों में 21 हजार से अधिक परीक्षार्थी उपस्थित
अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल के अनुसार, प्रथम पाली में 15,696



पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 10,579 उपस्थित रहे, जबकि 5,117 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 15,696 परीक्षार्थियों में से 10,422 ने परीक्षा दी और 5,274 अनुपस्थित रहे। इस प्रकार दोनों पालियों में कुल 21,001 परीक्षार्थी उपस्थित हुए और 10,391 अनुपस्थित रहे।
परीक्षार्थियों के परिजनों से किया संवाद
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद परीक्षार्थियों के परिजनों से बातचीत कर उनके ठहरने और आवागमन की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। प्रयागराज से आए कुछ परिजनों ने बताया कि वे एक दिन पहले झांसी पहुंचे थे और नगर निगम की

ओर से उपलब्ध कराए गए आश्रय स्थल पर निःशुल्क ठहरे थे। उन्होंने टैक्सी से आवागमन के दौरान अतिरिक्त किराया नहीं वसूले जाने की भी जानकारी दी। परीक्षार्थियों और उनके परिजनों को ठहरने में परेशानी न हो, इसके लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों ने नगर के रैन बसेरों का निरीक्षण किया। प्रशासन के अनुसार, रैन बसेरों में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था की गई थी। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि जिले के 37 परीक्षा केंद्रों पर 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को भी पीईटी आयोजित की जाएगी। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर प्रीति सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज के प्राचार्य सतीश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मध्य प्रदेश राज्यसभा उपचुनाव: पहले दिन किसी ने नहीं भरा नामांकन

संवाददाता
भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि, पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। उम्मीदवारों के पास पचां भरने के लिए 2 नवंबर तक का समय है। जरूरत पड़ने पर 12 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। यह सीट केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरगन के राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवार 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्र मध्य प्रदेश विधानसभा भवन स्थित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जाएंगे। सार्वजनिक अवकाश के दिन नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 3 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगी। उम्मीदवार 5 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और आवश्यकता होने पर 12 नवंबर को मतदान कराया जाएगा।

जून 2027 तक पूरा हो सकता है उज्जाव स्टेशन का पुनर्विकास, रेलवे जीएम ने किया निरीक्षण

संवाददाता
उज्जाव, उत्तर प्रदेश। उज्जाव रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य जून 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे नॉर्दन रेलवे के महाप्रबंधक (जीएम) राजेश पांडे ने स्टेशन पहुंचकर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी ली और निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।
आधी बिल्डिंग का काम आगे बढ़ा, गुणवत्ता पर जोर
निरीक्षण के बाद जीएम राजेश पांडे ने बताया कि स्टेशन के पुनर्विकास का काम जारी है। फिलहाल आधी बिल्डिंग का निर्माण काफी आगे बढ़ चुका है। इसके पूरा होने के बाद दूसरी तरफ का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जून 2027 तक पुनर्विकास का काम पूरा हो सकता है। इसके लिए रेलवे की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। जीएम ने कहा कि निर्माण के दौरान कुछ छोटी-मोटी कमियां सामने आती रहती हैं। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता उच्च स्तर की बनी रहे।

रवि बनकर जुनैद ने हिंदू महिला को प्रेम जाल में फंसाया आँटो चालक गिरफ्तार

इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का मामला, शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक शोषण करने का आरोप, चार साल के बच्चे के साथ भी कथित यौन उत्पीड़न
संवाददाता
इंदौर, मध्य प्रदेश। शहर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ लंबे समय तक शारीरिक शोषण और उसके चार साल के बेटे के साथ कथित अप्राकृतिक कृत्य का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
आँटो चालक ने अपनी पहचान छिपाई
पुलिस के अनुसार, मुकरीपुरा नरसिंह बाजार निवासी 28 वर्षीय महिला की मुलाकात वर्ष 2015 में एक आँटो चालक से हुई थी। महिला राजवाड़ा में खरीदारी के बाद अन्नपूर्णा क्षेत्र स्थित अपने घर लौटने के लिए आँटो तलाश रही थी। इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर अपना नाम रवि बताया और अपनी असली पहचान छिपाई। इसके बाद आरोपी महिला के संपर्क में बना रहा और शादी का झांसा देकर उसका शोषण



करने लगा। आरोप है कि उसने इंदौर के कालानी नगर, चंदन नगर, जूना रिसाला और महावर नगर सहित अलग-अलग इलाकों में किराए के कमरे लेकर महिला का कई वर्षों तक शारीरिक शोषण किया। आरोपी पर महिला के चार साल के बेटे के साथ भी अप्राकृतिक कृत्य करने का गंभीर आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पुष्टि और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत निर्माण कार्य की प्रगति परखी, महिला प्रतीक्षालय के नवीनीकरण के निर्देश, नेपाली यात्री की मौत के मामले में पुलिस से जानकारी लेने की बात कही



यात्री सुविधाओं में सुधार और महिला प्रतीक्षालय के नवीनीकरण के निर्देश
जीएम ने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना रेलवे की प्राथमिकता है। स्टेशन पर यात्री सुविधाओं से जुड़ी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। महिला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महिला प्रतीक्षालय का नवीनीकरण कराने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि यात्रियों और आम लोगों से मिलने वाली शिकायतों व सुझावों पर ध्यान देकर सुविधाओं में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

सादाबाद में छुटा सांड का आतंक पूर्व प्रधान समेत नौ लोग घायल, दो भैंसों की मौत

संवाददाता
सादाबाद, उत्तर प्रदेश। हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र के गांव मढ़नई और आसपास के इलाकों में पिछले दो दिनों से आतंक का पर्याय बने छुटा सांड ने सोमवार सुबह जमकर उत्पात मचाया। सांड के हमले में पूर्व प्रधान रामभरोसी समेत नौ लोग घायल हो गए। हमले में दो भैंसों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य भैंस और एक घोड़ी घायल हो गई। ग्रामीणों ने सांड को गांव से बाहर खदेड़ने का प्रयास किया, इसी दौरान वह दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। कुछ समय बाद सांड की भी मौत हो गई।
पूर्व प्रधान पर मंदिर में क्रिया हमला
सोमवार सुबह गांव मढ़नई में अचानक पहुंचे सांड ने लोगों और पशुओं पर हमला करना शुरू कर दिया। हमले में नाला हरनाम निवासी कारे सिंह, मढ़नई के पूर्व प्रधान रामभरोसी, अतर सिंह, विजेंद्र सिंह, बंटी, अनम, पुजारी पून पुरी, ऋषि और कंचना घायल हो गए। अचानक हुए हमले से गांव में चीख-पुकार मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। ग्रामीणों के अनुसार, पूर्व प्रधान रामभरोसी मंदिर में पूजा करने गए थे। इसी दौरान सांड ने उन पर हमला कर दिया। वह खुद को बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन सांड उन पर हावी हो गया। शोर सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह उन्हें सांड से बचाया।
दीवार से टकराकर बेहोश हुआ



सांड, बाद में मौत
ग्रामीणों ने साहस जुटाकर सांड को गांव से बाहर खदेड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान भागते समय वह एक दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। उसके दोबारा उठकर हमला करने की आशंका के चलते ग्रामीणों ने उसके पैर रस्सियों से बांध दिए। हालांकि, कुछ समय बाद सांड की मौत हो गई। गोसेवक राहुल कश्यप और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने जैसीबी से गड्ढा खुदवाकर सांड के शव का अंतिम संस्कार कराया। बेकाबू सांड ने ग्रामीणों के पशुओं पर भी हमला किया। इस दौरान तीन भैंस और एक घोड़ी घायल हो गई। ग्रामीण चोब सिंह, हेमंत, सत्यभान और ज्ञानदेव सहित अन्य लोगों ने अपने पशुओं को बचाने का प्रयास किया।
रविवार रात एदलपुर बरी चौराहे पर भी मचाया था उत्पात
ग्रामीणों के मुताबिक, इसी सांड ने रविवार रात एदलपुर बरी चौराहे पर भी उत्पात मचाया था। वहां उसने होमगार्ड कारे सिंह पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था।

घटना के कारण चौराहे पर काफी देर तक जाम लगा रहा। इसके अलावा एदलपुर निवासी पंकज की एक भैंस की भी सांड के हमले में मौत हो गई थी। लगातार दो दिनों तक हुई घटनाओं से आसपास के गांवों में भय का माहौल बना रहा।
घरों में दुबके ग्रामीण, सुरक्षा पर उठे सवाल
सांड के आक्रामक व्यवहार से भयभीत ग्रामीणों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए और गांव की गलियों में आवागमन प्रभावित हो गया। ग्रामीणों ने डायल 112 पर सूचना देकर पुलिस से मदद मांगी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को भी सांड के हमले से बचने के लिए मशकत करनी पड़ी। घटना के बाद क्षेत्र में छुड़ा पशुओं से लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आबादी वाले इलाकों में घूम रहे आक्रामक और निराश्रित पशुओं को समय रहते पकड़कर सुरक्षित आश्रय स्थलों तक पहुंचाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।